



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 843]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2004/आश्विन 8, 1926

No. 843]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2004/ASVINA 8, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 1071(अ).—यतः अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17-9-1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गए थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।

3. स्थिति की पिछली बार मार्च, 2004 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 30-9-2004 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के दो गुटों, जो अपने आधिपत्य का प्रयास करने के अतिरिक्त विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में भी संलिप्त हैं, के बीच चल रही जमीनी लड़ाई की वजह से अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसी सूचना है कि भूटान में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के शिविरों को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप यह संगठन असम में अपनी पैठ बनाने के लिए इन दो जिलों को अपने ठिकानों के रूप में प्रयोग कर रहा है। रिपोर्टों से अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों में अरुणाचल ड्रैगन फोर्स (ए.डी.एफ.), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) काडरों की मौजूदगी तथा उनके द्वारा आंदोलन चलाए जाने की भी पुष्टि हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विद्रोह के स्तर में कमी आई है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2005 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99—एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2004

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991

S.O. 1071(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March, 2004 and *vide* Notification bearing S.O. 437(E) dated 31st March, 2004, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2004. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency, with an ongoing turf war between two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN), who apart from striving for domination, are also indulging in unlawful activities. Consequent to closure of its camps in Bhutan, United Liberation Front of Assam is also reported to be using bases in these two districts to make forays into Assam. Reports also confirm the presence and movement of Arunachal Dragon Force (ADF), National Liberation Front of Arunachal Pradesh and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) cadres in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has brought down the level of insurgency. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2005 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.